631

Total Pages : 5 **Roll No. ----------**

LM-107

Judicial Process/ न्यायिक प्रक्रिया

Master of Law LLM-12/16/17)

Second Year, Examination 2021 (Winter)

Time: 2 Hours Max. Marks: 80

Note : This paper is of Eighty (80) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र अस्सी (80) अंकों का है जो दो (02) खण्डों, क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section – A /खण्ड–क

(Long Answer – type questions) /(दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note: Section 'A' contains Five (05) long-answer-type questions of Twenty (20) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only.

[2 x 20 = 40]

P.T.O.

नोट : खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बीस (20) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Q.1. Examine the laws made by judges in the context of amending powers of parliament under Article-368 of Indian Constitution.

न्यायाधीश निर्मित विधियों का भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद की शक्तियों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

Q.2. What do you understand by the term "Rule of Law"? Discuss the reasoning of the concept of the term" Rule of Law" in the light of the case Menka Gandhi vs. Union of India.

"विधि के शासन" से आप क्या समझते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए।

Q.3. Supreme court is the watchdog of Indian constitution. Justify the above statement with the help of decided cases.

उच्चतम न्यायलय संविधान का संरक्षक है। न्यायिक निर्णयों की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए।

Q.4. Discuss the various theories of justice as propounded by the renowned jurists.

विधिशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किये गये विभिन्न प्रकार के न्याय के सिद्धान्तों की चर्चा कीजिए।

Q.5. What is the role of judicial process in establishing the social order.

न्यायिक प्रक्रिया का सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में क्या योगदान है।

Section – B / खण्ड– ख

(Short-answer-type questions) / लघु उत्तरों वाले प्रश्न

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of Ten (10) marks each. Learners are required to answer any Four (04) questions only.

[4 x 10 = 40]

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दस (10) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Q.1. Discuss the contribution of M.C.Mehta in the context of judicial activism.

न्यायिक सक्रियता के सन्दर्भ में एम0जी0मेहता के योगदान की चर्चा कीजिए।

P.T.O.

Q.2. What steps have been taken by the Parliament of India regarding the guidelines issued by the Supreme Court with respect to Sexual harassment of female workers at workplace.

उच्चतम न्यायलय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जो दिशा निर्देश दिये हैं उनके क्रियान्वयन के लिए भारतीय संसद द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गये हैं।

Q.3. Is judiciary in the name of judicial activism interfering with the law making functions of parliament?

क्या न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। समझाइये।

Q.4. Directive Principles of State Policy of Indian Constitution are from time to time being converted into Fundamental Rights by the Supreme Court of India. Explain the above statement in the light of relevant cases.

भारत के संविधान में दिये गये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उच्चतम न्यायालय द्वारा समयानुसार मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिए।

Q.5. How laws are framed through Judicial decisions? Explain.

न्यायिक निर्णयों द्वारा विधि निर्माण किस प्रकार होता है। समझाइये।

Q.6. What do you understand by judicial review? How it helps in preservation of constitutional values?

न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करता है?

Q.7. The Preamble of Indian Constitution provides for Social, Economic and Political justice to all its citizen. Explain.

भारत के संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध करवाया है। स्पष्ट कीजिए।

Q.8. Public Interest Litigations are a necessary in today's scenario. Explain.

लोकहित वाद वर्तमान समय की आवश्यकता है। स्पष्ट कीजिये।

———————————